

करती है, इस शर्त के अधीन रहते हुए, कि यदि केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि इस प्रकार की कार्यवाही करना लोकहित में आवश्यक है, केन्द्रीय सरकार सभी या किसी एक राज्य सरकारों की बाबत शक्तियों के ऐसे प्रत्यायोजन को प्रतिसंहत कर सकेगी या वह स्वयं अधिनियम की धारा 5 के उपबन्धों का अवलंब ले सकेगी।

[संख्या 1(38)/86-पी. एन.]

का. पा. गीताकुमार, सचिव

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(Department of Environment, Forests and Wildlife)

New Delhi, the 22nd September, 1988

### NOTIFICATION

S.O. 881(E).—In exercise of the powers conferred by section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 the Central Government hereby delegates the powers vested in it under section 5 of the Act to the State Governments of Goa and Jammu & Kashmir subject to the condition that the Central Government may revoke such delegation of powers in respect of all or any one of the State Governments or may itself invoke the provisions of section 5 of the Act, if in the opinion of the Central Government such a course of action is necessary in public interest.

[No. 1(38)/86-PL]

K. P. GEETHAKRISHNAN, Secy.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 480]  
No. 480]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 22, 1988/भाद्रपद 31, 1910  
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 22, 1988/BHADRA 31, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

वित्त मंत्रालय  
(आर्थिक कार्य विभाग)  
(वैकिंग प्रभाग)

नयी दिल्ली, 22 सितम्बर, 1988

अधिसूचना

का.मा. 882(घ).--नोबहुन विकास निधि समिति (उत्पादन)  
अधिनियम, 1986 (1986 का 66) की धारा 16 की उपधारा (1)  
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त  
मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की दिनांक 3 अप्रैल, 1987 के का.  
मा. सं. 305(घ) की अधिसूचना के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार  
एतद्वारा भारतीय नोबहुन ऋण तथा निवेश कम्पनी लि. को, जो कम्पनी  
अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्टर्ड कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत  
कार्यालय (निर्भोत हाऊस), 254-बी, डा. एम.बैसेंट रोड, बम्बई-400025  
है अधिहित व्यक्ति के रूप में नियुक्त करती है और उक्त अधिहित व्यक्ति  
को उक्त अधिनियम की धारा 4 और 5 के अधीन प्रयोग किये जाने योग्य  
शक्तियों और कार्यों का निम्न प्रकार प्रत्यायोजन करती है अर्थात् :-

- (1) उत्पादन से पूर्व, नोबहुन विकास निधि समिति और शिपयार्डों  
या पोतनिर्माताओं के बीच सम्बन्ध संबंधियों की शर्तों के अनुसार,  
पोत निर्माण का प्रत्येक खरण पूरा हो जाने पर, शिपयार्डों

या पोत निर्माताओं को नोबहुन कम्पनी और शिपयार्ड को, जैसी  
भी स्थिति हो, अथवा पोतनिर्माता को भुगतान इस शर्त के  
अधीन किया जाएगा कि प्रथम खरण के अन्त में भुगतान की  
गणि जारी करने से पूर्व, अधिहित व्यक्ति द्वारा केन्द्रित सरकार  
से पूर्वनिर्धारित प्राप्त कर लिया जाएगा;

- (2) नोबहुन विकास निधि समिति के उत्पादन से पूर्व, समिति द्वारा  
किये गये ऐसे भुगतानों के लिए, जिसके संबंध में संविधानगत  
दारिद्र्य भी विद्यमान हों, समर्थनकारी वातावरणों का मुआना  
इस शर्त पर किया जाएगा कि मूलधन और ब्याज को चुकौती  
के मामले में, नोबहुन कम्पनी की ओर से कोई भुगतान नहीं की  
गया है अथवा बचक की स्थिति में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनु-  
सूचित पुनरुद्धार को किसी योजना के अनुसार निशुल्क का  
पुनर्निर्धारण कर दिया गया है;
- (3) नोबहुन विकास निधि समिति के उत्पादन से पूर्व, समिति द्वारा  
निष्पादित गारंटियों अथवा प्रतिगारंटियों के संबंध में किसी  
शिपयार्ड से प्राप्त योग्य यात्राओं के बारे में किसी विवादों  
द्वारा गारंटी अथवा प्रतिगारंटी का सत्यापन करने का पूरा  
में रकमों का भुगतान;